ई.आर.सी.पी. पर हंगामा, दो बार स्थगित हुआ सदन

किरोड़ी मीणा ने कहा, ''आप तो अनुमति नहीं ले सके, हमारे सी.एम. ने तो बनते ही मध्यप्रदेश से सहमति ले ली, यह कांग्रेस पचा नहीं पा रही है

- विपक्ष का आरोप, ''पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ सरकार ने बड़ा विश्वासघात किया''
- 'ई.आर.सी.पी. को हटाते हैं, यह पार्वती काली सिंध हो गई, आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो'
- निर्दलीय बोले, ''83 विधायकों के क्षेत्र में पानी कम हो जाएगा, यह पीढ़ी तो बद्दुआ देगी ही, आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी''

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में ई.आर.सी.पी. पर आधे घंटे की चर्चा के बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर 13 जिलों की जनता के हितों पर कुठाराघात करने का अरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस विधायक और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल वेल में आ गए और लगातार सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने के नारे लगाने लगे। हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही दो बार 20-20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने पार्वती कालीसिंध (पीकेसी) धोखा है के नारे लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि पीकेसी-ईआरसीपी के नए प्रोजेक्ट में 13 जिलों को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा, नए समझौते में पानी पहले से कम मिलेगा। चर्चा में कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ भजनलाल सरकार ने जितना बड़ा विश्वासघात किया, उतना किसी ने नहीं किया। बोहरा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यसभा में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में जलशक्ति मंत्री ने कहा था कि 75 फीसदी वाटर डिपेंडेबिलिटी नहीं है इसलिए नेशनल परियोजना नहीं बनेगी। नेशनल परियोजना आपने घोषित नहीं की। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि अब ई.आर.सी.पी. को हटाते हैं, अब यह पीकेसी हो गई है। आप जनता की ओखों में धूल झोंक रहे हो। जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। मंत्री ने कहा था कि 2400 एमसीएम पानी मिलेगा। यह पहले से तय हो चुका है, मंत्री ने सदन को गुमराह किया। मंत्री को यह जवाब ही नहीं देना चाहिए था। पूर्वी राजस्थान बिना सिंचाई के रहेगा।

चर्चा में बोलते हुए आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि पीकेसी ईआरसीपी के एमओयू की कॉपी सदन में नहीं रखी। हो सकता है जल संसाधन मंत्री ने कॉपी देखी ही नहीं हो। सदन में एमओयू को रखिए ताकि यह तो पता लगे कि एमओयू में नया क्या है?

चर्चा में डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने नए एमओयू पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा और कहा कि जलशक्ति मंत्री ने बताया था कि 3510 का जो प्रस्ताव था, उससे 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा। जब पानी कम हो जाएगा, तो सिंचाई कहां से होगी। सिंचाई के सपने तो पूर्वी राजस्थान बंद कर दें। उन्होंने कहा कि 1999 के बाद मध्यप्रदेश ने तो डेम बना लिए। 1200 एमसीएम पानी तो एमपी आज काम ले रहा है। यूनुस खान ने कहा कि किरोड़ी मीणा से राय ली जाती तो राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं होता। 83 विधायकों के क्षेत्र में पानी कम हो जाएगा।

विधायकों की ओर से उठाई गई चिंता पर बोलते हुए मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा ने कहा कि कई बार चर्चाएं हुई और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब ईआरसीपी के तहत पानी के बंटवारे को मंजूरी देने मना कर दिया था। मीणा ने कहा कि आप तो अनुमति नहीं ले सके, जबकि हमारे सीएम ने तो बनते ही मध्यप्रदेश से सहमति ले ली, यह कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने जलजीवन मिशन का पैसा ईशरदा डैम में लगा दिया।

डॉ किरोड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते तो 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य को खर्च करना पड़ता। इसे केन-बेतवा परियोजना की थीम पर पीकेसी बनाकर रास्ता निकाला, इसे एनपीपी बनाया जिससे 90 फीसदी पैसा केंद्र देगा। इससे पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को अशोक गहलोत ने पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि 75 फीसदी वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाओ, तब हम इसे मंजूरी देंगे। केंद्रीय जल आयोग भी 75 फीसदी को मानता है। वहीं इंदिरा गांधी के जमाने से प्रावधान है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए डिपेंडेबिलिटी 75 फीसदी ही चाहिए। इंट्रा स्टेट में 50 फीसदी चल जाएगा, लेकिन इंटर स्टेट में 75 फीसदी ही चाहिए। मध्यप्रदेश ने जो बांध बनाए वो इंट्रा स्टेट था। किरोड़ी ने कहा कि 3510 एमसीएफ पानी की बात कहां से आई।

इससे पहले जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा संशोधित पीकेसी लिंक योजना का केंद्रीय जल आयोग परीक्षण कर रहा है। पिछली सरकार ने कम बांध भरने का टारगेट रखा था। नई पीकेसी लिंक परियोजना से 40 फीसदी ज्यादा आबादी को पानी मिलेगा। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल ने बड़ा विजन दिखाया है। उन्होंने कहा कि एमओयू के अनुसार डीपीआर बनाई जाएगी, डीपीआर के बाद ही पानी की मात्रा की गणना होगी।

जलसंसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी कॉपोरशन बनाया, लेकिन बजट केवल 200 करोड़ का दिया। कॉर्पेशन को कहा कि आप जमीन बेचो, लेकिन 14 हजार करोड़ का प्रबंध करो। फिर भी कहते रहे कि केंद्र इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगा तो हम करेंगे, बजट तो दिया ही नहीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रिपता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर मंगलवार को प्रातः शासन सचिवालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। शर्मा ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रिपता महात्मा गांधी एवं ज्ञात-अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधीजी के प्रिय भजनों 'वैष्णव जन तो तेने कहिये, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो, श्री राम जय राम, तू ही है तो सहारा' को सुना। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी-कर्मचारियों ने भी मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

'प्रदेश के बाहर आयुष्मान योजना में नहीं हो रहा इलाज'

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज चिरंजीवी योजना के बाद आयुष्मान योजना का मुद्दा भी उठा। निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने स्थगन प्रस्ताव के लिए आयुष्मान योजना का मुद्दा उठाया। हालांकि उनके स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर बोलते हुए चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को आयुष्मान के साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि आयुष्मान योजना में एमओयू नहीं होने के कारण प्रदेश के बाहर इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को योजना के तहत इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए दिल्ली, गुजरात व अन्य राज्यों में जाते हैं। लेकिन उन मरीजों को आयुष्मान योजना में इलाज नहीं मिल रहा है।उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द आयुष्मान योजना के तहत एमओयू किया जाए।

मैडम तुसाद में स्वामी रामदेव की मोम की प्रतिकृति का अनावरण

जयपुर, (का.सं.)। मैडम तुसाद, न्यूयार्क में आज स्वामी रामदेव की मोम की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। यह भारतीय संस्कृति, संन्यास और सनातन योग परम्परा के वैश्विक प्रभाव की अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता और प्रतिष्ठा का परिचायक है।

कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि मैडम तुसाद, न्यूयॉर्क में 200 से ज्यादा बड़े आयकॉन्स के फिगर लगे हैं जिनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा तथा शाहरूख खान आदि हैं किन्तु वर्ल्ड के उन 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक संन्यासी को इन्होंने जो सम्मान दिया वह एक संन्यासी का गौरव नहीं अपितु पूरे भारत का गौरव है। आज पूरी दुनियां की निगाहें भारत के योग व आयुर्वेद पर हैं। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस तथा मेड बाई अमेरिका के कान्सैप्ट पर चल रहा है। योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी का जो मूमेंट पतंजलि से चलाया था उसकी लहर अब पूरी दुनिया में हैं।

स्वामी ने बताया कि इस प्रतिकृति को बनाने में लगभग 200 आर्टिस्ट का पुरुषार्थ तथा लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह कास्ट का विषय नहीं हैं, यह एक कॉन्सेप्ट है जिसमें भारत और भारतीयता को, भारत के एक संन्यासी को स्थान दिया है। हम इसके लिए मैडम तुसाद की टीम के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वामी रामेदव का सम्मान

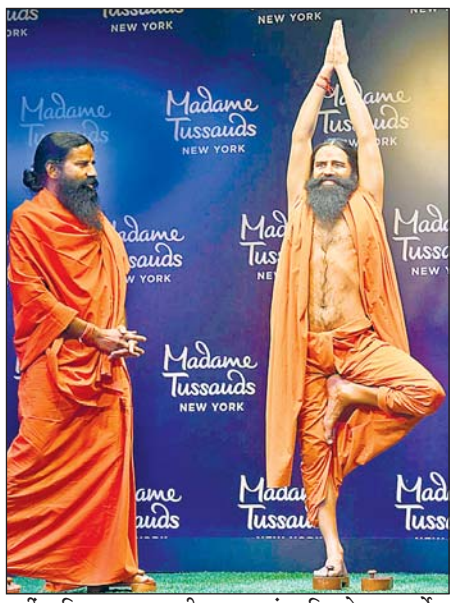

नहीं अपितु यह भारत की सनातन संस्कृति, योग, आयुर्वेद, भारत की सनातन संस्कृति, हमने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है।

सांगा बाबा पदयात्रा 4 को

जयपुर। सांगा बाबा सांगानेर से 4 फरवरी को शिला माता आमेर तक पदयात्रा अयोजित की जाएगी।सुनील कोठारी ने बाताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हमारे प्यारे जयपुर शहर को दो हिस्सो मे बांटने का निर्णय किया गया था। जिसके बाद से ही जयपुर शहर को एक बनाए रखने के लिए जयपुरवासियों द्वारा महारा जैपुर-प्यारा जयपुर के तत्वावधान में मुहीम से जुड़कर सभी नागरिको ने जयपुर शहर के प्रमुख मंदिरों मे महाआरती कर सरकार द्वारा जयपुर शहर को दो भागो बांटने के निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य किया। जयपुरवासियो ने श्री सांगा बाबा मंदिर सांगानेर मे संकल्प लिया था कि सरकार द्वारा इस निर्णय के वापस लिए जाने पर एक संकल्प पदयात्रा श्री सांगा बाबा से चांदपोल हनुमान मंदिर होते हुए आमेर शिला देवी मंदिर तक जाएगा।

'ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में अगर भ्रष्टाचार हुआ, तो इसकी जांच होगी'

- खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में मनोज न्यागली के प्रश्न का जवाब दिया

जयपुर, (वि.सं.)। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में केवल टी-शर्ट व अन्य सामग्री की खरीद पर हुए ख़र्च परभ्रष्टाचार हुआ है तो राज्य सरकार वित्त विभाग के माध्यम से इसकी पूरी जांच कराएगी।

कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा विधायक मनोज न्यागली ने कहा कि इसमें अधिकारी सरकार को आंकड़े गलत देकर गुमराह करते हैं। राठौड़ ने कहा कि यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 126 करोड़ रुपए की राशि इनकी खरीद पर व्यय कर दी गई। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के बजट से भी 4 गुना अधिक बजट इन खेलों के आयोजन में किया गया और किसी भी नए स्टेडियम अथवा स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि मुख्य खेल अधिकारी के चयन को लेकर भी किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी।

इससे पहले विधायक मनोज कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खेल मंत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल-2022 में 40 करोड़ 92 लाख 56 हजार 890 रुपए की राशि व्यय हुई। इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल-2023 में 155 करोड़ 46 लाख 72 हजार 500 रुपए की राशि व्यय हुई।

राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आधार पर राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं के चयन या सरकारी सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

कर्नल राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी।

उप मुख्यमंत्री दियाकुमारी ने मंगलवार को अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं और जनता के बीच धूमधाम से मनाया। उन्होंने बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया।

'खनन अभियान के नाम पर पुलिस कर रही ज्यादती'

जयपुर, (वि.सं.)। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए बूंदी जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन के संबंध में जो अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में बूंदी पुलिस बिना खनन विभाग के अधिकारियों के यह तय कर लेती है कि कहां अवैध खनन हो रहा है और कहां नहीं। बूंदी पुलिस अधीक्षक की ओर से 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत एक प्रेसनोट जारी करके बताया गया कि उन्होंने अवैध खनन कर रहे वाहनों को जब्त किया हैं। इस गलत कार्रवाई के खिलाफ जब जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया तो उन्हीं वाहनों को लेकर एक दूसरा प्रेसनोट जारी किया जाता हैं।

'नए जिला कारागृह बनने पर हो सकेगा आबादी क्षेत्र में जेलों की समस्या का समाधान'

- कारागार मंत्री की ओर से चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया
- विधानसभा में उठा मुख्यमंत्री को जेल से मिली धमकी का मुद्दा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पिछले दिनों मुख्यमंत्री को जेल से मिली धमकी का मुद्दा उठा। इस पर सरकार ने माना कि जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा है और ज्यादातर जेल शहर के बीच में हैं, ऐसे में जल्द ही नई जेल बनाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को धमकी देने के सवाल पर मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि कई बार जेल में स्मगलिंग और मोबाइल की वारदात के मामले सामने आते हैं, लेकिन जल्द ही इन जेलों से कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा। इस पर अध्यक्ष ने कहा जिलों में नहीं तो संभाग पर ज्यादा कैपेसिटी वाली जेल बनाई जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नए जिला कारागृह बनने पर कैदियों को इनमें शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे आबादी क्षेत्र में कारागृहों के संचालन तथा इनमें क्षमता से अधिक बंदियों को रखने की समस्या का समाधान हो सकेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर कारागार मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर के केंद्रीय कारागृह और अन्यंत्र स्थानांतरण को लेकर सवाल लगाया। इस पर जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सरकार कैदियों की संख्या को देखते हुए और सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखकर शहर से बाहर जेल बनाएगी। वहां कैदियों को हस्तांतरित किया जाएगा। इस लिए नई जेल बनाई जाएगी ताकि इस दबाव को कम किया जा सके। मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 19 जिले नए बनाए। उन सभी जिलों में भी जेल बनेगी, इसके बाद जिन जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा है वहां उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। विधायकरफीक खान ने कहा कि शहर के बीच में जेल असुरक्षित है और जेल से मुख्यमंत्री तक को धमकी मिल रही है। इस मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार चाहती तो पांच साल में वित्तीय स्वीकृति जारी कर जेल बना सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई. अब हमारी सरकार बनाएगी। इस बीच रफीक खान ने फिर सवाल खड़े किए और कहा कि मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है।इस पर मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कैपेसिटी एक अलग चीज है। कई जगह मोबाइल और स्मगलिंग की वारदात आती रहती है, लेकिन ये सही है कि सरकार नई जेल बनाने पर काम करेगी, ताकि जो खतरा शहरों के बीच में बनी जेल से बना हुआ है, वो खत्म हो।
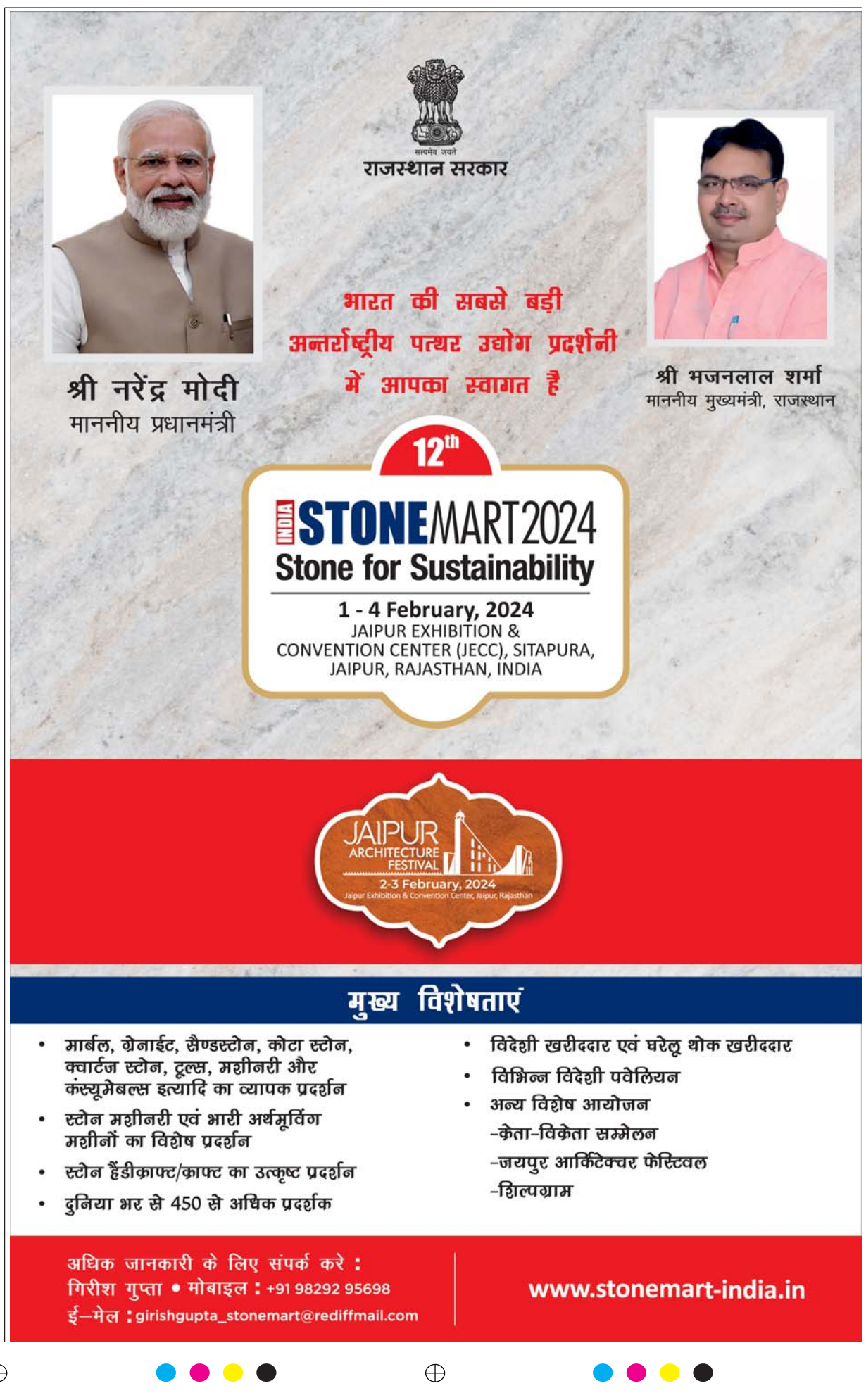
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय वित्तीय स्वीकृति दिलाकर आबादी क्षेत्र में चल रही जयपुर सेन्ट्रल जेल को अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।